

**मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों से  
समाचार प्रसारण में भेदभाव**

\* 119. श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल :  
क्या सूचना श्री. प्रसारण मंत्री यह बताने की  
कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में  
आकाशवाणी के इन्दौर और भोपाल केन्द्रों में  
भेद-भावपूर्ण तथा एकपक्षीय समाचार प्रसारण  
के विरोध में प्रदर्शन किये गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या  
है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रदर्शनकारियों  
द्वारा दिये गये ज्ञापन तथा उनकी मांगों का  
ज्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री  
बलराम साठे) :** (क) जो, हाँ ?

(ख) जिस माननीय सदस्य ने यह  
प्रश्न पूछा है उनके द्वारा और भारतीय  
जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्त्तियों द्वारा 16-1-  
82 को आकाशवाणी के भोपाल केन्द्र के  
सामने प्रदर्शन किये गये थे । मध्य प्रदेश के  
कुछ विधायकों के नेतृत्व में भारतीय जनता  
पार्टी के कार्यकर्त्तियों द्वारा 21-1-82 को  
आकाशवाणी के इन्दौर केन्द्र के सामने भी  
प्रदर्शन किया गया था ।

(ग) यह आरोप लगाया गया था कि  
भारतीय जनता पार्टी को गतिविधियों को  
आकाशवाणी द्वारा उचित रूप से कवर  
नहीं किया गया था । तथ्यात्मक रूप से  
यह सच नहीं है ?

**Questionnaire issued by Law Commission  
on the efficacy of the present  
judicial system**

\* 120. SHRIMATI AMARJIT  
KAUR:

SHRI RAMANAND YADAV:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Law Commission has circulated an elaborate questionnaire to elicit the opinion of the legal profession on the efficacy of the present judicial system; and

(b) if so, what are the points on which the opinion has been sought and which are the forums, agencies and legal experts to whom the questionnaire has been sent?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGAN NATH KAUSHAL):  
(a) Yes, Sir,

fb) A copy of the Questionnaire, which is self-explanatory, is laid on the Table. The Questionnaire has been issued to various institutions and functionaries such as the Supreme Court and the High Courts, Attorney-General, Solicitor-General and Additional Solicitor-General, the Bar Council of India and the High Court Bar Associations Advocates-General of the States, Deans of Faculties of Law, Political Science and Sociology of 17 prominent universities, Institutes of Management at Hyderabad, Calcutta and Bombay, Director of the Indian Law Institute, Mayors of Municipal Corporations of Bombay, Calcutta, Bangalore, Hyderabad and Nagpur, Chambers of Commerce & Industry and the various Trade Unions. Steps have also been taken by the Law Commission to publish the Questionnaire in the leading law journals of the country.

re? Appendix CXXI, Annexure No. 23]